प्रादेशिक समाचार बुलेटिन,
आकाशवाणी, लखनऊ।

प्रसारण तिथि : 24.07.2024 प्रसारण समय : 19:20 बजे

मुख्य समाचार :–

1. रेलवे के विकास के लिए प्रदेश को 19 हजार 848 करोड़ रुपये किए गए आवंटित : केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में रेलवे का बजट 18 गुना बढ़ा।
2. मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा– एसडीएम और तहसीलदार जिस तहसील में तैनात हैं, वहीं करें निवास।
3. लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत करेगा आयोजित।

और

4. वाराणसी के लोगों के लिये काशो विश्वनाथ धाम में विशेष द्वार से दर्शन की व्यवस्था शुरू : स्थानीय पहचान पत्र दिखाकर भक्त कर सकेंगे प्रवेश।

———————

केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए कुल 92 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक यूपीए के कार्यकाल

में उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 1109 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर 19 हजार 848 करोड़ रूपये कर दिया गया है, जो पिछली सरकार की तुलना में 18 गुना ज्यादा है। बाइट.....

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए उन्नीस हजार आठ सौ अड़तालीस करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। जिस तेजी से पिछले दस वर्षों में उत्तर प्रदेश में रेलवे का काम हुआ है उसका आप किसी भी पैमाने पे देखे तो वो एक नया रिकार्ड है।

श्री वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछल 10 वर्षों में 4 हजार 9 सौ किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जो पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की लंबाई से अधिक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे ट्रैकों का 100: विद्युतीकरण हो चुका है। साथ ही प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में 14 सौ 90 फ्लाइओवर व अंडरपास का निर्माण हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन सुगम हुआ है और एक्सीडेंट्स की संख्या कम हुई है।

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए 40 से अधिक प्रोजेक्ट्स को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का पुर्नविकास कई चरणों में होगा। उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं। कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए जनप्रतिनिधियों से फीडबैक

भी लिया जा रहा है, बड़ी सख्या में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।

———————————

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व मं विपक्ष लगातार यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि केन्द्रीय बजट सरकार को बचाने का प्रयास था।

उधर, लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। अध्यक्ष ओम बिडला ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि सदन को शून्यकाल के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना सही नहीं है।

संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं ने सदन की सुचारू कार्यवाही चलाने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन उपयुक्त नहीं है।

———————————

जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करें। साथ ही सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर सात दिन के अन्दर इस आशय का सर्टिफिकेट उपलब्ध करायेंगे।

———————————

सीमा सुरक्षा बल– बीएसएफ, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल– सीआईएसएफ और रेलवे सुरक्षा बल– आरपीएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को अपन–अपने संगठन में शामिल करने की तैयारियां कर ली हैं। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को सीमासुरक्षा बल में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु में छूट मिलेगी। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने भी कहा कि पूर्व अग्निवीरों

को कांस्टेबल के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट के साथपूर्व अग्निवीरों का बल में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

———————

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

जिंगल

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है।

———————

सर्वोच्च न्यायालय के नीट–यूजी परीक्षा–2024 दोबारा न कराने के आदेश के बाद देशभर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए आज से कॉउन्सलिंग प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। शीर्ष न्यायालय के फैसले पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि नीट घोटाले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षा एजेंसी

को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। श्री प्रधान ने कहा कि समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्र की है तथा विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये की निंदा की है।

———————————

सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। यह पहल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में एक मील का पत्थर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं।

इस साल 29 जुलाई से तीन अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, व्यक्तिगण से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स इन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं उनमें क्या हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं।

———————————

सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की कार्य अवधि से संबंधित अपने नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार नई कार्य अवधि सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी। शीर्ष न्यायालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि छुट्टियों और दूसरे तथा चौथे शनिवार को अदालत के कार्यालय बंद रहेंगे। नए नियम एक अगस्त से लागू होंगे।

———————

वाराणसी के लोगों के लिये काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिये कल से अलग द्वार खोल दिया गया है। अब काशी वासियों के लिए श्रावण सोमवार और त्यौहार के दिनों के अलावा प्रतिदिन सुबह 4 स 5 बजे तक स्पर्श दर्शन और शाम 4 से 5 बजे तक झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। काशीवासियों को इस द्वार से प्रवेश के लिए बस अपना वाराणसी के पते का पहचान पत्र दिखाना होगा।

श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि काशी वासी बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन कर पाएं, इसके लिए 13 जुलाई से 21 जुलाई तक काशी द्वार से ट्रायल किया गया था। इस दौरान 11 हजार 777 भक्तों ने बाबा के दर्शन किये। ट्रायल की सफलता के बाद अब इस व्यवस्था को नियमित कर दिया गया है।

(समाप्त)